

UPSC CSE 2018 MAINS PAPER 6 OCTOBER 07, 2018 LAW OPTIONAL PAPER - I QUESTION PAPER

EGT-P-LAW

## विधि / LAW

## प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks : 250

## प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लपे हुए हैं ।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अ-थ किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में छाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

## Question Paper Specific Instructions

*Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :*

*There are EIGHT questions divided in TWO SECTIONS and printed both in HINDI and in ENGLISH.*

*Candidate has to attempt FIVE questions in all.*

*Questions no. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, any THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each section.*

*The number of marks carried by a question / part is indicated against it.*

*Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.*

*Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.*

*Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.*

## खण्ड A

## SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) 'सहकारी परिसंघवाद' एवं 'प्रतियोगी परिसंघवाद' शब्दों से आप क्या समझते हैं ? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत का संविधान 'प्रतियोगी परिसंघवाद' की संकल्पना पर आधारित है, न कि 'सहकारी परिसंघवाद' की संकल्पना पर ?

What do you understand by the terms 'cooperative federalism' and 'competitive federalism' ? Do you agree with the view that the Indian Constitution is based on the concept of 'competitive federalism' and not on the concept of 'cooperative federalism' ?

10

- (b) प्रशासनिक शक्तियाँ/कार्य हमेशा 'विधिसम्मत शासन' के सिद्धान्त के विरोध में नहीं होते हैं । उदाहरण सहित विवेचना कीजिए ।

Administrative powers/actions are not always in conflict with the 'rule of law' principle. Discuss with illustration.

10

- (c) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्धीन 'राज्य' की संकल्पना के परिवर्तनशील आयामों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

Critically evaluate the changing dimensions of the concept of 'State' under Article 12 of the Constitution of India.

10

- (d) "नैसर्गिक न्याय एक ऐसा तैयार फार्मूला नहीं है, जिसे सभी परिस्थितियों में कटोर एकरूपता के साथ मापा जाए ।" टिप्पणी कीजिए । निर्णयजन्य विधि का उल्लेख कीजिए ।

"Natural justice is not a made to order formula which has to be fitted to all situations with an iron-bound uniformity." Comment. Refer to case laws.

10

- (e) "सरकार के संसदीय स्वरूप के अंगीकरण के साथ अनुच्छेद 53(1) के अर्धीन निहितकारी खण्ड काफी हद तक निरर्थक हो जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रालय में निहित होती है ।" भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा एवं स्थिति के संदर्भ में, उपर्युक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । यह भी बताइए कि यदि भारत का राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह को नहीं मानता है, तो उसके क्या-क्या परिणाम होंगे ।

"With the adoption of Parliamentary form of government, the vesting clause under Article 53(1) remains to a great extent meaningless, as real executive power lies in the Ministry." Critically examine the above statement in the context of the status and position of the President of India under the Indian Constitution. Also answer, if the President of India does not accept the advice of the Prime Minister, what consequences would follow.

10

- Q2.** (a) संविधान में, विशेष रूप से संविधान के अध्याय IV में और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन, परिकल्पित सामाजिक न्याय की संकल्पना का परीक्षण कीजिए ।  
Examine the concept of social justice as envisaged in the Constitution, more particularly in Chapter IV of the Constitution and under Article 14 of the Constitution. 20
- (b) सिविल कर्मचारी को पदच्युति, निष्कासन अथवा सेवाओं की श्रेणी में अवरोध के विरुद्ध क्या-क्या संवैधानिक रक्षोपाय उपलब्ध हैं ? क्या ये अधिकार सार्वजनिक निगम के किसी कर्मचारी को भी उपलब्ध हैं ? कानूनी प्रावधानों तथा निर्णयजन्य विधि का संदर्भ देकर विवेचना कीजिए ।  
What are the constitutional safeguards available to a civil servant against dismissal, removal or reduction in rank of services ? Are these rights also available to an employee of a public corporation ? Discuss with reference to statutory provisions and case law. 15
- (c) भारत में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का सर्वोत्तम पद्धति या तरीका क्या होगा ? अपने विचार व्यक्त कीजिए और उनके समर्थन में तर्क दीजिए ।  
What would be the best way or method for the appointment of judges in High Courts and the Supreme Court in India ? Give your views and support your views with reasons. 15
- Q3.** (a) भारत में स्थानीय निकायों के प्रचालन में क्या-क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं ? क्या यह सफलता की कहानी है या कि कुछ और है ?  
What are the major challenges in the functioning of local bodies in India ? Does it talk about success story or something else ? 20
- (b) क्या राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पर आधारित है ? विवेचना कीजिए । असंख्य शक्तियों के इस्तेमाल में, राज्यपाल का 'विवेक' किस चीज़ से गठित होता है ? कानूनी प्रावधानों एवं संगत निर्णयजन्य विधि का संदर्भ देकर व्याख्या कीजिए ।  
Is the Governor's post dependent on the pleasure of the President ? Discuss. What exactly constitutes the 'discretion' of the Governor while exercising numerous powers ? Explain with reference to statutory provisions and relevant case law. 15
- (c) प्रत्यायोजित विधान की सांविधानिकता की विवेचना कीजिए । प्रत्यायोजित विधान की परिसीमण क्या है ? व्याख्या कीजिए ।  
Discuss the constitutionality of delegated legislation. What are the limits of delegated legislation ? Explain. 15

- Q4. (a)** “वाक् स्वातंत्र्य में अन्तर्निहित प्रेस की स्वतंत्रता नागरिक के वाक् स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य से उच्चतर धरातल पर स्थित नहीं है, और न ही प्रेस को सामान्य नागरिक से भिन्न कोई ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा ‘वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ और ‘वाक् एवं अभिव्यक्ति’ शब्दों के बीच विभेदन भी कीजिए।  
“The liberty of the press implicit in the freedom of speech stands on no higher footing than the freedom of speech and expression of a citizen, and no privilege is attached to the press as such distinct from the ordinary citizen.” Explain this statement and also distinguish the term ‘freedom of speech and expression’ and ‘speech and expression’.
- 20
- (b)** “अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य में आपातकाल का अधिरोपण हमेशा से विवाद का विषय रहा है।” इस पृष्ठपट में, किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा के परिणामों की व्याख्या कीजिए।  
“Imposition of Emergency in a State under Article 356 has always been a matter of controversy.” In this backdrop, explain the consequences of proclamation of Emergency in a State.
- 15
- (c)** किन परिस्थितियों में, भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, संबंधित पक्षकारों के अलावा अन्य व्यक्ति, सुने जाने के अधिकार के लिए रिट याचिकाएँ दायर कर सकता है ? ऐसी याचिकाओं की परिसीमाओं का भी उल्लेख कीजिए।  
Under what circumstances, does a third party, apart from concerned parties, have locus standi to move writ petitions before the High Court or the Supreme Court in India ? Also point out the limitations of such petitions.
- 15

**खण्ड B**  
**SECTION B**

**Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :**

**Answer the following questions in about 150 words each :**

**10×5=50**

- (a) अंतर्राष्ट्रीय विधि की परम्परागत एवं आधुनिक परिभाषाओं के बीच भिन्नताओं की व्याख्या कीजिए । वर्तमान संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि के बढ़ते हुए विषय-क्षेत्र एवं महत्त्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Explain the distinctions between traditional and modern definitions of international law. Critically examine the growing scope and importance of international law in the present context.

10

- (b) “जहाँ प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है वहाँ शरण समाप्त हो जाती है ।” उपर्युक्त कथन का प्रत्यर्पणीय व्यक्तियों और प्रत्यर्पण अपराधों के विजंघ संदर्भ में, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

“Where Extradition begins Asylum ends.” Critically examine the above statement with special reference to extraditable persons and extradition crimes.

10

- (c) सामान्यतः यह समझा जाता है कि “अधिकार एवं कर्तव्य सहसंबंधी होते हैं” । फिर भी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन का विकास कर्तव्योन्मुख होने की अपेक्षा अधिकारोन्मुख अधिक हुआ है । ऐसा क्यों हुआ है ? विविध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार लिखतों की सहायता से व्याख्या कीजिए । क्या आप ‘मानवाधिकार आंदोलन’ के बजाय ‘मानव कर्तव्य आंदोलन’ के विषय में सोच सकते हैं ?

It is generally viewed that “Rights and Duties are correlative”. However, the International Human Rights Movement has developed more as rights-oriented than duties-oriented. Why has this happened ? Explain with the help of various International Human Rights instruments. Can you think of a ‘Human Duty Movement’ instead of a ‘Human Rights Movement’ ?

10

- (d) ‘अंतर्राष्ट्रीय संधि’ की परिभाषा दीजिए और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों के बढ़ते हुए महत्त्व की व्याख्या कीजिए । क्या बहुपक्षीय संधि का परिसमापन किया जा सकता है ? यदि हाँ, तो किन आधारों पर ? व्याख्या कीजिए ।

Define ‘International Treaty’ and explain the growing importance of treaties in Modern International Law. Can a multilateral treaty be terminated ? If so, on what grounds ? Explain.

10

- या आप इस कथन से सहमत हैं कि “वैश्वीकरण एक आवश्यक बुराई है” ? आई.एम.एफ., और आई.सी.आर.डी. द्वारा विकासशील देशों, विशेषकर भारत के संदर्भ में, संरचनात्मक समाधान कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से चलाई गई सुधार प्रक्रिया की विवक्षाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Do you agree with the statement that “the Globalization is a necessary evil” ? Critically examine the implications of the reform process undertaken by the IMF and ICRD by way of structural adjustment programmes and policies on developing countries, with special reference to India.

10

- Q6.** (a) “महाद्वीपीय शेल्फ को तटवर्ती राज्य के भू-खण्ड का प्राकृतिक विस्तारीकरण माना जाता था ।” अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) की संगत निर्णयजन्य विधि की सहायता से, महाद्वीपीय शेल्फ के सीमांकन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

“Continental Shelf was regarded as the natural prolongation of the land mass of the coastal state.” Critically examine the Delimitation of the Continental Shelf with the help of relevant case law of the International Court of Justice (ICJ).

20

- (b) अंतर्राष्ट्रीय विवाद की परिभाषा दीजिए । विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा बाध्यकारी समाधान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए । अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान में, ए.डी.आर. विधियों के बढ़ते हुए महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Define International Dispute. Explain the difference between peaceful settlement of disputes and compulsive settlement of disputes. Critically examine the growing importance of ADR methods in International Dispute settlement.

15

- (c) “प्रमुखतः विवर्धभिक्कार (वीटो पावर) के कारण सुरक्षा परिषद की सदस्यता लोकतंत्रिक नहीं है । इस दृष्टि में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए तथा अन्य देशों को अधिक सदस्यता दी जानी चाहिए, ताकि राष्ट्रों के समुदाय की जनसांख्यिकीय संरचना प्रतिबिंबित हो ।” व्याख्या कीजिए ।

“Membership of the Security Council is not democratic mainly because of its veto power. In view of that, the U.N. Security Council should be expanded and should give more membership to other countries reflecting the demographic composition of the community of nations.” Explain.

15

- Q7. (a)** “चार जेनेवा कन्वेंशनों (1949) और 1977 के उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉलों के कुछ प्रावधानों ने आज अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि के रुढ़िक सिद्धान्तों (जस कोरस) का दर्जा प्राप्त कर लिया है।” क्या आप उपरोक्त कथन से सहमत हैं ? चार जेनेवा कन्वेंशनों के साईं अनुच्छेद 3 के आलोक में, अपने तर्कों का औचित्य बताइए।

“Certain provisions of the four Geneva Conventions (1949) and their additional protocols of 1977 have assumed the status of customary principles (ius cogens) of IHL, today.” Do you agree with the above statement ? Justify your arguments in the light of common Article 3 of the four Geneva Conventions.

20

- (b) अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों के संदर्भ में, आतंकवाद की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, प्रभावशाली रणनीति के रूप में, क्या आप प्रति-आतंकवाद (काउंटर-टेररिज्म) को रक्षक मानते हैं ? उदाहरणों सहित आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था प्रभावशाली है ? व्याख्या कीजिए।

Explain the concept of terrorism in the context of current technological developments. Do you justify counter-terrorism as an effective strategy to deal with terrorist activities ? Is the existing international legal regime effective in dealing with emerging new terrorist threats ? Explain.

15

- (c) पेरिस तथा बर्न व्यवस्थाओं (रेजीमों) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि “व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) और कुछ नहीं है, बल्कि केवल पेरिस तथा बर्न कन्वेंशनों की पुनरावृत्ति मात्र है।” विवेचना कीजिए।

Explain the differences between Paris and Bern regimes. Do you agree with the statement that “The Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) is nothing, but mere repetition of the Paris and Bern Conventions.” Discuss.

15

- Q8. (a)** “अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः राज्यों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं हितों से संबद्ध है।” अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों तथा गैर-राज्य निकायों के स्थान के उल्लेख के साथ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“International law is primarily concerned with Rights, Duties and Interests of States.” Critically examine the statement with reference to the place of Individuals and Non-State entities in International law.

20

- (b) क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि “1972 की स्टॉकहोम उद्घोषणा से प्रारम्भ होकर पर्यावरण संबंधी अबाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय लिखतों पर निर्भरता बढ़ गई है” ? इस प्रवृत्ति का विकास क्यों हुआ है और क्या ये लिखतें मंधियों की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी हुई हैं ? व्याख्या कीजिए ।

Do you agree with the statement that “Beginning with the Stockholm Declaration of 1972, there has been an increased reliance upon non-binding international instruments dealing with environment.” ? Why has this trend developed and have these instruments been more useful than treaties ? Explain.

15

- (c) सामान्यतया वह विचार व्यक्त किया जाता है कि “20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र ने शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो कुछ किया, 21वीं शताब्दी में आर्थिक एवं व्यापार संबंधों के लिए विश्व व्यापार संगठन वही भूमिका निभाने जा रहा है” । राज्यों की राजनीतिक संप्रभुता से आर्थिक संप्रभुता की ओर परिवर्तनशील धारणा के संदर्भ में उपर्युक्त कथन पर चर्चा कीजिए ।

It is generally viewed that “What the U.N. did in the 20<sup>th</sup> century for maintenance of peace and security, the W.T.O. is going to play the same role on economic and trade relations in the 21<sup>st</sup> century”. Discuss the above statement in view of the changing notion of political sovereignty to economic sovereignty of States.

15